Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE)

Summary for the month of February, 2020

Important events for the month of February, 2020 are as follows:

(a) A day long interactive meeting with the States and Union Territories (UTs) under the chairmanship of Secretary, MSDE was held on 18.02.2020 at Pravasi Bharatiya Kendra, New Delhi. Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/ Secretaries of Skill Development of States and UTs and Managing Directors of State Skill Development Missions (SSDMs) were present at the meeting along with senior officials from MSDE, NSDC (National Skill Development Corporation). Shri Mahendra Nath Pandey Hon'ble Minister,SDE, and Shri R.K Singh, Hon'ble Minister of State, SDE also addressed the gathering. Detailed discussions were held on various points including States' suggestions and feedback for next version of PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana), how to synergise Central and State level skilling schemes and increasing State's participation and ownership in implementation of various skilling schemes.

(b) Demand for Grants (DFG) meeting was conducted on 19.02.2020 by the Standing Committee on Labour in the Parliament. Secretary, MSDE provided responses to the queries pertaining to MSDE which were raised by the Standing Committee members.

(c) Ministry of Skill development collaborated with Ministry of Women and Child to have a daylong National Conference on 14.02.20 on Policy Framework for skilling of Women and Children. Hon'ble Minister, MSDE, Hon'ble Minister MWCD, Secretary, MSDE, Secretary, MWCD, along with other stakeholders, officials of both the Ministries and others participated in the Conference.

(d) A meeting was held by Hon'ble Minister, MWCD, with Secretary MSDE, on 17.2.20 to design and implement a course on Emergency Medical Technical Course for Care Givers.

(e) Minister of State, MSDE, held separate meeting with the Sector Skill Councils related to Power (19.2.20), Electronics (19.2.20), Mining (20.2.20), Green Jobs (20.2.20), Hydrocarbon (25.2.20) and IT & ITEs (28/2/20)

(f) A workshop on Gender Study was held on 21/2/20 to identify constraints on female participation in skills training.

(g) The meeting of Common Costs Committee was held on 26/2/20 wherein a number of policy decisions were taken.

(f) The 24th Meeting of the National Skills Qualifications Committee was held on 27/2/20, wherein a number of Qualification Packs were approved, and major policy decisions taken to streamline the process of approvals.

(g) A brain storming session was held with the Entrepreneur Development institutes of the States, along with NGOs in the field of entrepreneurship to help design the new programme of Entrepreneurship.

(h) The new initiatives and milestones achieved under the programme SANKALP (Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood) programme during the month are as under:

- Multi-stakeholder Consultative meeting was held on 10.02.2020 at Delhi for identifying pilots on skilling, reskilling & upskilling of 'Safai Karamcharis' in Uttar Pradesh and Maharashtra.

- A presentation on 'Opportunities of Integrating Skilling with Gram Panchayat Development Plan (GPDP)' was made at the National Colloquium of State Secretaries of RD&PR (Rural Development and Panchayati Raj) and Heads of SIRDPRs (State Institute for Rural Development and Panchayati Raj) at Hyderabad on 14.02.2020.
- MoU was signed between MSDE and National Instructional Media Institute (NIMI) for establishment of NIMI SANKALP Cell for implementation and support of Mahatma Gandhi National Fellowship (MGNF) programme under Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP) programme.

(i) MoU has been signed with Ordnance Factory Board for re-skilling of surplus workers in Feburary 2020.

(j) A meeting of all RDSDEs (Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship) was convened on 19.02.2020 to discuss the Functional Requirement Specification (FRS) for new apprenticeship portal. A walk-through of portal features was done and feedback was invited from all the stakeholders.

(k) The new initiatives and milestones achieved under Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE) programme during the month are as under:

- 33 Industrial Training Institutes (ITIs) have signed tripartite agreement to participate in the programme. Till date a total of 244 ITIs have signed Performance based grant agreement.
- MoU has been signed between UT of Jammu & Kashmir and Govt. of India to implement the STRIVE project. Till date 32 States/UTs have signed MoUs to implement STRIVE.
- 240 officials have been trained under NSQF (National Skills Qualification Framework) compliance training. Till date 13,750 officials have been trained under NSQF.
- The draft Recruitment, Training and Career Progression Policy document for Craft instructors/Trainers of ITIs has been sent for approval of Recommendation Committee of Norms & Courses.
- Video Conference was held for selected Industry clusters under the STRIVE project to support them in implementation of Industry Apprentice Initiative (IAI) Plan.
- 193 ITIs have been physically visited by external agency for grading under phase 2. Till date 11,486 ITIs have been physically visited by the external agency.
- Letters have been sent to various states requesting faster fund transfer from state treasury to implementing agencies under the STRIVE project.

(l) NSDC signed/ finalized number of MOUs with other Ministries, States and Corporates for carrying out specific skilling assignments: Jal Jeevan Mission (RPL training for mason, electrician, plumber), Tamil Nadu House (RPL for their contractual Staff in Housekeeping), Bridgestone (to reskill tyre fitters), etc.

******

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई)

फरवरी 2020 माह का मासिक सारांश

फरवरी 2020 माह के महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

(क) सचिव, एमएसडीई की अध्यक्षता में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के साथ 18.02.2020 को प्रवासी भारतीय केंद्र, नई दिल्ली में पूरे दिन की संवादात्मक बैठक हुई। बैठक में एमएसडीई, एनएसडीसी (राष्ट्रीय कौशल विकास निगम) के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के कौशल विकास सचिव तथा राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम) के प्रबंध निदेशक उपस्थित थे। माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री, डॉ. महेंद्रनाथ पाण्डेय तथा माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री, श्री राजकुमार सिंह ने भी सभा को संबोधित किया। राज्यों के सुझावों तथा पीएमकेवीवाई (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना) के अगले वर्जन हेतु फीडबैक, केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर कौशलीकरण स्कीम में कैसे तालमेल रखा जाए, राज्यों की भागीदारी में वृद्धि तथा विभिन्न कौशलीकरण स्कीमों के कार्यान्वयन का स्वामित्व सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

(ख) अनुदान मांग (डीएफजी) की बैठक श्रम संबंधी स्थायी समिति द्वारा 19.02.2020 को संसद में आयोजित की गई थी। सचिव, एमएसडीई ने स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा एमएसडीई से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए थे।

(ग) कौशल विकास मंत्रालय ने महिला तथा बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर 14.02.2020 को महिलाओं तथा बच्चों के कौशलीकरण के नीतिगत संबंधी ढांचे पर पूरे दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में माननीय मंत्री, एमएसडीई, माननीय मंत्री, एमडब्ल्यूसीडी, सचिव, एमएसडीई, सचिव, एमडब्ल्यूसीडी के साथ अन्य हितधारकों, दोनों मंत्रालयों के अधिकारियों तथा अन्यों ने भाग लिया।

(घ) देखभाल करने वालों के लिए आपाकालीन चिकित्सा तकनीकी पाठ्यक्रम संबंधी एक पाठ्यक्रम तैयार करने तथा उसे कार्यान्वित करने के लिए माननीय मंत्री, एमडब्ल्यूसीडी की अध्यक्षता में 17.02.2020 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सचिव, एमएसडीई उपस्थित थे।

(ङ) माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री ने पॉवर (19.02.2020), इलेक्ट्रॉनिक (19.02.2020), माइनिंग (20.02.2020), ग्रीन जॉब (20.02.2020), हाइड्रोकार्बन (25.02.2020) तथा आईटी एंड आईटीई (28.02.2020) से संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों के साथ अलग-अलग बैठक आयोजित की।

(च) कौशल प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी संबंधी कमी को पहचानने के लिए जेंडर अध्ययन संबंधी एक कार्यशाला 21.02.2020 को आयोजित की गई।

(छ) सामान्य लागत समिति की बैठक 26.02.2020 को आयोजित की गई, जिसमें नीतिगत निर्णय लिए गए।

(ज) राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति की 24वीं बैठक 27.02.2020 को आयोजित की गई, जिसमें अर्हता पैक अनुमोदित किए गए, तथा अनुमोदन की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए प्रमुख नीतिगत निर्णय लिए गए।

(झ) नए उद्यमशीलता कार्यक्रम तैयार करने में सहायता करने के लिए उद्यमशीलता क्षेत्र में लगे एनजीओ सहित राज्यों के उद्यमशील विकास संस्थानों के साथ एक विचारमंथन सत्र आयोजित किया गया।

(ञ) माह के दौरान संकल्प (आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन तथा ज्ञान जागरूकता) कार्यक्रम के अंतर्गत नई पहलें तथा उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

- उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में 'सफाई कर्मचारियों' के कौशलीकरण, पुन: कौशलीकरण तथा कौशल उन्नयन से संबंधित प्रायोगिकों की पहचान करने के लिए दिल्ली में 10.02.2020 को बहु-हितधारक परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई।
- आरडी एंड पीआर (ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज) के राष्ट्रीय राज्य सचिवों के संघ तथा एसआईआरडीपीआर (ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज के राज्य संस्थान) के अध्यक्षों के समक्ष 14.02.2020 को हैदराबाद में 'ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ कौशलीकरण को एकीकृत करने के अवसर' से संबंधित एक प्रस्तुती दी गई थी।
- एमएसडीई तथा राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान (एनआईएमआई) के बीच आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन तथा ज्ञान जागरूकता (संकल्प) कार्यक्रम के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप (एमजीएनएफ) कार्यक्रम की सहायता तथा कार्यान्वयन के लिए एनआईएमआई संकल्प प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ।

(ट) फरवरी 2020 में अधिशेष कर्मियों के पुन: कौशलीकरण के लिए आयुध निर्माण बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।

(ठ) नए शिक्षुता पोर्टल के लिए कार्यात्मक आवश्यकता विशिष्टता (एफआरएस) पर विचार करने के लिए 19.02.2020 को सभी आरडीएसडीई (कौशल विकास और उद्यमशीलता क्षेत्रीय निदेशालय) की बैठक बुलाई गई। पोर्टल की विशेषताएं देखी गईं तथा सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त की गई।

(ड) माह के दौरान औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) कार्यक्रम के अंतर्गत नई पहलें तथा उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

- 33 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) ने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए त्रिपक्षीय समझौते हस्ताक्षरित किए हैं। अब तक 244 आईटीआई ने निष्पादन आधारित अनुदान समझौते हस्ताक्षरित किए हैं।
- स्ट्राइव परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। स्ट्राइव को कार्यान्वित करने के लिए अब तक 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।
- 240 अधिकारियों को एनएसक्यूएफ (राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा) अनुरूप प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब तक 13,750 अधिकारियों को एनएसक्यूएफ के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- आईटीआई के शिल्प अनुदेशकों/प्रशिक्षकों हेतु भर्ती, प्रशिक्षण तथा कैरियर प्रगति नीति दस्तावेज प्रारूप मानदंड तथा पाठ्यक्रम की सिफारिश समिति को अनुमोदन के लिए भेजा गया है।
- स्ट्राइव परियोजना के अंतर्गत चुने गए उद्योग क्लस्टरों को उद्योग शिक्षु पहल (आईएआई) योजना के कार्यान्वयन में उन्हें सहायता करने के लिए वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया।
- 193 आईटीआई का चरण 2 के अंतर्गत ग्रेडिंग के लिए बहारी एजेंसी द्वारा वास्तविक रूप से दौरा किया गया है। अब तक बहारी एजेंसी द्वारा 11,486 आईटीआई का दौरा वास्तविक रूप से किया गया है।
- स्ट्राइव परियोजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्य कोष से तेजी से निधि अंतरण के लिए विभिन्न राज्यों को अनुरोध पत्र भेजे गए हैं।

(ढ) एनएसडीसी ने विशेष कौशलीकरण कार्यों: जल जीवन मिशन (मेसन, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर के लिए आरपीएल प्रशिक्षण), तमिलनाडु हाउस (हाउसकिपिंग में उनके ठेका कर्मचारियों के लिए आरपीएल), ब्रिजस्टोन (टायर फिटर के पुन: कौशलीकरण के लिए), आदि को पूरा करने के लिए अन्य मंत्रालयों, राज्यों तथा निगमों के साथ कई समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं/अंतिम रूप दिया है।

******